तापमान

भोपाल	23.0°	28.0°
इंदौर	23.0°	31.0°
जबलपुर	22.0°	29.0°
ग्वालियर	26.0°	31.0°
सागर	23.0°	29.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 267, पृष्ठ 12)
श्रावण, शुक्ल चतुर्दशी संवत् 2083
बुधवार, 26 अगस्त 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naidunialive.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब नहीं ...

खेल... एशियाई खेलों में अपने पदकों का सूखा दूर करने उतरेगी...

व्यापार... भारत में सफल होने पर कोई अचानक गायब नहीं ...

देश-विदेश... नेतन्याहू का दावा- ईरान ने बेटे की हत्या की ...

'स्कूलों में हिजाब पर रोक, तय यूनिफॉर्म का पालन हो'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- समान यूनिफॉर्म से बनता है बराबरी का माहौल, ड्रेस कोड तय करने का अधिकार स्कूल का

नईदुनिया ब्यूरो, प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि स्कूलों में तय यूनिफॉर्म का पालन जरूरी है, क्योंकि इससे छात्रों में समानता की भावना बनी रहती है और संस्थान की पहचान कायम रहती है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने नाबालिग छात्रा की याचिका खारिज कर दी। छात्रा ने स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड के साथ हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी।

कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति देना यूनिफॉर्म की अवधारणा के खिलाफ होगा। इससे स्कूल के अनुशासन और ड्रेस कोड तय करने का अधिकार संस्था के बजाय अलग-अलग छात्रों के हाथ में चला जाएगा। याचिकाकर्ता छात्रा ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है और उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धार्मिक अधिकारों के तहत इसकी अनुमति मिलनी चाहिए। छात्रा का कहना था

कि वह कक्षा 6 से 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही है। स्कूल प्रशासन ने अदालत में कहा कि सभी छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड लागू है और किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से व्यवस्था प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल प्रशासन को अपने नियम तय करने का अधिकार है। यदि किसी समय हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति दी गई थी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा के लिए अधिकार बन जाएगा। अदालत ने कहा कि स्कूल छात्रा की आस्था पर रोक नहीं लगा रहा है, बल्कि केवल संस्थागत अनुशासन और यूनिफॉर्म के पालन की अपेक्षा कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिजाब को इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हिजाब विवाद का मामला पहले कर्नाटक से शुरू हुआ था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में स्कूल ड्रेस कोड को मान्यता देते हुए हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं माना था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ की राय अलग-अलग रही थी और मामला अभी लंबित है।

राहुल गांधी अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करतेः रिजिजू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पितृसत्ता खत्म करने वाले बयान पर सवाल उठाए हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी केवल हिंदू परंपराओं पर ही सवाल क्यों उठाते हैं। उन्होंने पूछा कि अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर राहुल गांधी बात क्यों नहीं करते। रिजिजू ने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और बेटियों को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी से सभी महिलाओं के अधिकारों और स्थिति पर समान रूप से चर्चा करने की अपील की। राहुल गांधी ने 22 अगस्त को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्रता और पितृसत्ता के मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए महिलाओं को पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक बताया था। राहुल गांधी ने कहा था कि महिलाओं की पहचान उनके पिता, पति या बेटे से नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान से होती है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के तीन रूपों का उल्लेख करते हुए शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता की बात कही थी। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी, जबकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं की।

राहत : जमाखोरी पर सख्ती चीनी हुई 18 प्रतिशत सस्ती

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः चीनी की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने लगी है। सरकार की ओर से चीनी आयात की अनुमति और जमाखोरी पर सख्ती के बाद चीनी के भाव रिकॉर्ड स्तर से करीब 18 प्रतिशत तक गिर गए हैं। मिलों से निकलने वाली चीनी यानी एक्स-मिल कीमत अब 55 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। पिछले सप्ताह यही भाव 67 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर था।

केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। इसके साथ ही बड़े खरीदारों पर स्टॉक सीमा लागू की गई है और राज्यों को जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। चीनी उद्योग के अनुसार एक्स-मिल कीमतों में गिरावट का असर जल्द ही थोक और खुदरा बाजार पर भी दिखाई देगा। आमतौर पर एक्स-मिल और खुदरा कीमतों में 7 से 8 रुपये प्रति किलो का अंतर रहता है। वर्तमान में देशभर में चीनी का औसत थोक भाव 58.29 रुपये और खुदरा भाव 63.05 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है।

सरकार ने व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा भी तय की है। महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा चीनी आयात को कर मुक्त किया गया है और निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक रोक लगाई गई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग 280 से 285 लाख टन के बीच है। ऐसे में देश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

खास-खबरें

प्रकाश राज ने किया एसआईआर का विरोध

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरु : अभिनेता और फिल्म निर्माता प्रकाश राज ने कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सिविल सोसायटी संगठन एक सितंबर को बेंगलुरु में 'इलेक्शन कमीशन चलो' अभियान शुरू करेगा। प्रकाश राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसआईआर पर रोक लगाने के लिए संगठन अदालत का रुख करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2019 में प्रकाश राज के खिलाफ कई राज्यों के मतदाता पहचान पत्र रखने को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी।

राम रहीम 17वीं बार जेल से बाहर

नईदुनिया ब्यूरो, रोहतक : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। मंगलवार सुबह वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकलकर सिरसा स्थित डेरे पहुंचा। काफिले में कई वाहन और पुलिस सुरक्षा शामिल थी। साध्वियों से यौन शोषण मामले में सजा के बाद यह 17वीं बार है, जब राम रहीम पैरोल या फरलो पर बाहर आया है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने बार-बार रिहाई पर सवाल उठाए हैं।

परीक्षा को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन

नईदुनिया ब्यूरो, पटना : बिहार के पटना में टीआरई-4 परीक्षा में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्र पीटी-मेन परीक्षा, नकारात्मक अंक व्यवस्था हटाने और 100 प्रतिशत डोमिसाइल की मांग कर रहे थे। मंगलवार को छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और जवानों के बीच झड़प हुई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में लाठीचार्ज किया।

जांच समिति दोबारा बनाने की मांग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने हाई पावर जांच समिति दोबारा गठित करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में काम कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अभी लंबित है और इसका निपटारा नहीं हुआ है।

कैबिनेटः प्रदेश में विकास को गति देने के लिए 10,630 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

सड़क, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा पर जोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 10 हजार 630 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को 12 मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपये के ऋण के लिए शासकीय गारंटी देने का अनुमोदन किया। इसके अलावा 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सिवनी-बालाघाट 91.64 किलोमीटर मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। यह मार्ग सिवनी, बालाघाट, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की निर्धन और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक 1,740 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इनमें पेंशन, सहायता योजनाएं, दिव्यांगजन कल्याण और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय उज्जैन के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इससे स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा और प्रशासन को मजबूती मिलेगी।

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम योजना के तहत 2026-27 से 2030-31 तक 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अतिथि गृहों के उन्नयन एवं संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की मंजूरी दी। साथ ही आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को कार्रवाई के लिए अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी गई। महिला टी-20 विश्व कप क्रिकेट 2025 (दृष्टिबाधित) में स्वर्ण पदक विजेता मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मंत्री विजय शाह पर केस की अनुमति नहीं देगी सरकार

प्रदेश सरकार कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं देगी। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। चर्चा के दौरान मंत्री विजय शाह भी मौजूद थे। बैठक में अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के पीछे शाह की ओर से कई बार सार्वजनिक माफी मांगने का तर्क दिया गया। चर्चा के समय अधिकारियों को बाहर भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव की मौजूदगी में निर्णय लिया गया।

राहुल-खड़गे ने मोदी को लिखा पत्र

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना के सवालों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि जनगणना की प्रक्रिया तय करने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल नहीं होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है। उन्होंने बिहार और तेलंगाना में अपनाई गई प्रक्रिया जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

'नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने' की बात गैर-राजनीतिकः गडकरी

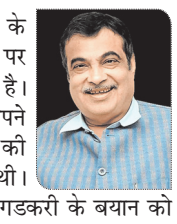

नईदुनिया ब्यूरो, नागपुरः केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने वाले बयान पर मंगलवार को उनके कार्यालय ने सफाई दी है। कार्यालय ने कहा कि गडकरी ने यह बात अपने लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को देने के संदर्भ में कही थी। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दरअसल, गडकरी के बयान को कुछ रिपोर्टों में उनके राजनीतिक भविष्य और सेवानिवृत्ति से जोड़कर देखा गया था। इसके बाद उनके कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया। गडकरी ने 23 अगस्त को पुणे के काटोल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि अब वह पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकते। जब वह काम कर सकते थे, तब उन्होंने किया।

6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हथियार और पोस्टर बरामद

▸▸ जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की कार्रवाई, शोपियां और पुलवामा से 8 संदिग्ध हिरासत में

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने चेकिंग अभियान के दौरान छह संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, इनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े पांच पोस्टर बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनके आतंकी नेटवर्क और हथियारों के स्रोत की जांच कर रही हैं। वहीं, पुलवामा जिले में भी सुरक्षाबलों ने कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई यरवान जंगल क्षेत्र में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान की गई। गिरफ्तार लोगों के पास से एक पिस्तौल, 12 कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। इससे पहले सोपोर के मंजसीर इलाके में सुरक्षाबलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर हथियार बरामद किए थे। अधिकारियों के मुताबिक, एक खाली पड़े घर से एक एके-47 राइफल, तीन मैगजीन, 72 कारतूस, चार हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी बरामद किया गया। मामले की जांच जारी है। सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और उनके सहयोगी नेटवर्क के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। बरामद हथियारों और गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले अप्रैल में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दो पाकिस्तानी आतंकी और उनके मददगार शामिल थे। इनमें एक आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरेरा था, जो 16 साल से फरार चल रहा था।

कनाडा की झील का नाम 'लेक अमेरिका' रखने पर विचारः ट्रंप

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से जुड़ी प्रसिद्ध झील लेक ओंटारियो का नाम बदलने की इच्छा जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह इसका नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' रखने पर विचार कर रहे हैं। लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका और कनाडा ने एक-दूसरे पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। हालांकि, झील का नाम बदलने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है और न ही कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई है।

बवंडर से 300 घरों को नुकसान, 41 घायल

पेरिस, एजेंसीः फ्रांस के एक गांव में सोमवार देर रात 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए टॉरनेडो ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में 41 लोग घायल हुए हैं, जबकि करीब 300 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों की छतें पूरी तरह उड़ गईं। सबसे ज्यादा असर करीब एक हजार आबादी वाले पोमास गांव में देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, यहां कई घर रहने

योग्य नहीं बचे हैं। टॉरनेडो के बाद करीब 5 सेंटीमीटर आकार के ओले भी गिरे, जिससे नुकसान और बढ़ गया। फ्रांस के परिवहन मंत्री फिलिपे तबारो ने बताया कि तूफान के कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं, कई सड़कें बंद करनी पड़ीं और हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी के साथ कुछ उड़ानें रद्द की गईं। राजधानी पेरिस के हवाई अड्डों पर भी इसका असर पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में 120 से अधिक बचावकर्मियों को तैनात किया है। घायलों में से 15 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। फ्रांस में हर साल औसतन 40 से 50 टॉरनेडो दर्ज किए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर बवंडर कमजोर होते हैं।

सैन्य रणनीति ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक प्रभाव जारी, सैन्य क्षमता के लिए लगातार तैयारी जरूरी...

राजनीतिक हितों की रक्षा का एक माध्यम है सेनाः चौहान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली : देश के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध और राजनीति को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि सेना राजनीतिक इच्छा का विस्तार होती है और किसी भी देश के राजनीतिक हित सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सेना उन हितों की रक्षा करने वाले कई माध्यमों में से एक है।

नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर आयोजित एक कार्यक्रम में जनरल चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने प्रूशियाई सैन्य विचारक कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि युद्ध दूसरे माध्यमों से राजनीति को आगे बढ़ाने का तरीका है। पूर्व सीडीएस ने कहा कि लोकतंत्र में जब सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल प्रयोग का निर्णय लेती है, तब सेना की

दो प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, सरकार को सैन्य विकल्प उपलब्ध कराना और दूसरी, सरकार में यह विश्वास पैदा करना कि वह अपनी जरूरत के अनुसार विकल्पों का इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि सैन्य विकल्प अचानक तैयार नहीं होते। इसके लिए शांतिकाल में लगातार प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास और संभावित परिस्थितियों की योजना बनाना जरूरी होता है। सैन्य नेतृत्व को ऐसे विकल्प तैयार करने होते हैं, जिनका उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जा सके।जनरल चौहान ने कहा कि हर सैन्य विकल्प के साथ जोखिम जुड़ा होता है। कमांडरों और नेताओं को इन जोखिमों और राजनीतिक उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभियान का सक्रिय चरण समाप्त हो चुका है, लेकिन इसका रणनीतिक प्रभाव अभी भी बना हुआ है। भारत के अलावा विदेशों में भी रणनीतिक विशेषज्ञ इस ऑपरेशन का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सैन्य अभियान का आकलन केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए।

इसमें अभियान से मिली सीख, सामने आई कमियों को दूर करने के प्रयास, आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप और वैश्विक अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। पूर्व सीडीएस ने कहा कि बदलते युद्ध के तरीकों और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत करना समय की जरूरत है।